International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 6, Nov.-Dec., 2023, Impact Factor: 7.326

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा

डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह

असिस्टेण्ट प्रोफेसर हिन्दी, इन्दिरा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौरीगंज, अमेठी

मनुष्य पशुओं से अपनी चिन्तन क्षमता के कारण अलग है। चिन्तन का सर्वश्रेष्ठ रूप है– 'शिक्षा'। शिक्षा यूँ तो 'सीखने एवं सिखाने की क्रिया है', परन्तु व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी समाज में निरन्तर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। यह मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों को विकसित तथा व्यवहार को परिष्कृत करती है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गाँधी जी के अनुसार[1] "शिक्षा से तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास वे है।" इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि– "मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।"[2]

शिक्षा के इन्हीं व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं अपने नागरिकों के मूल अधिकार 'शिक्षा' को समयानुकूल एवं प्रसंगानुकूल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर शिक्षा आयोगों एवं 'शिक्षा नीति' की घोषणा किया जाता रहा है। इसी क्रम में डॉ0 के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को प्रस्तुत किया, जिसे सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। यह विचारणीय है कि नई शिक्षानीति 2020 के केन्द्र में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा घोषित सतत विकास एजेण्डा 2030 का लक्ष्य 4(SDG-4) है। भारत सरकार द्वारा इसे 2015 में अपनाया गया है। SDG-4 में वर्ष 2030 तक "सभी के लिए समवेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य है।[3] इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को 'समर्थन और अधिगम' को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेण्डा के सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य और लक्ष्य (SDG) प्राप्त किए जा सकें।

नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथामिक शिक्षा/स्कूली शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में कहा गया है–"वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखे हीं और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखे। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या – समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अन्तर्सम्बन्धों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें।"[4]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गयी है। इसके उद्देश्यों के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross Enrollment Rate –सकल नामांकन दर) के साथ–साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति में 'स्कूल शिक्षा' की वर्तमान 10+2 वाली व्यवस्था के स्थान पर 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नए ढाँचे को पुनर्गठित किया गया है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष के बच्चे 10+2 वाले ढाँचे में शामिल नहीं है। स्कूली शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान निम्नवत है–

- नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो उसे 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। इसमें–
- पाँच (5) वर्ष की फाउण्डेशनल स्टेज (Foundational stage) –3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
- 3 वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (prepatratory stage) – ग्रेड 3, 4, 5

- 3 वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण– ग्रेड 6, 7, 8
- 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण– ग्रेड 9, 10, 11, 12

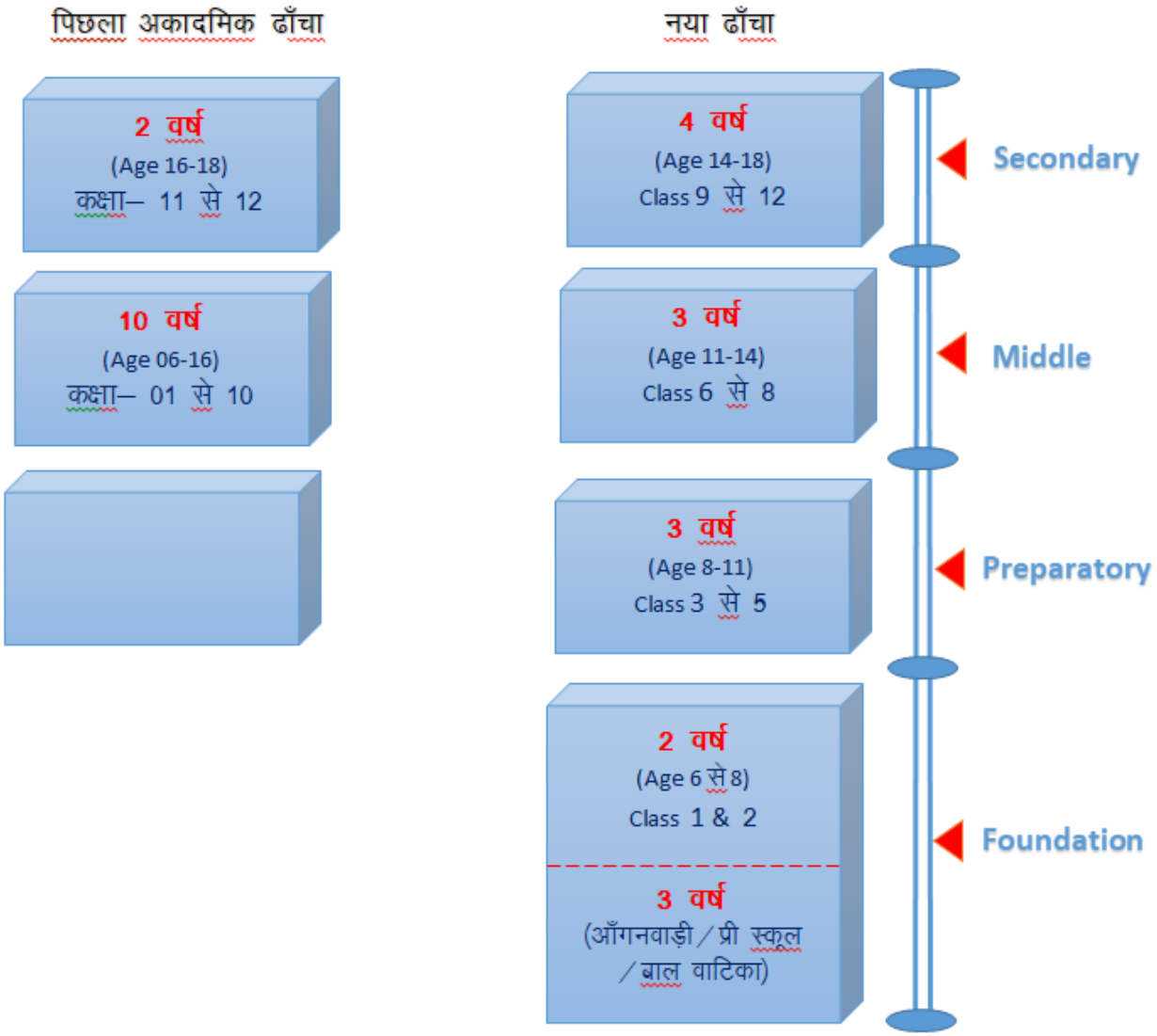

नए ढाँचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो ।

फाउण्डेशन स्टेज में 5 वर्षीय लचीले, बहुस्तरीय खेल / गतिविधि आधारित अध्ययन और ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे। ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है।

प्रीप्रेटेटी स्टेज 3 वर्ष की होगी जिसमें जो फाउण्डेशन स्टेज की खेल–खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इसमें पढ़ने लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित शामिल होंगे।

मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषयों के बीच परस्पर सम्बन्ध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सेकण्डरी स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे जो विषय उन्मुख शिक्षा क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे। इस स्टेज में विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव में लचीलापन होगा। विद्यार्थियों की इच्छानुसार ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11–12 में अन्य कोर्स के चुनाव का विकल्प रहेगा।

उपर्युक्त सभी स्तरों पर पाठ्य चर्या और शिक्षा विधि का समग्र केन्द्र बिन्दु शिक्षा प्रणाली को रहने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 के स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।[5]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषायी विविधता के संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत–

- कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कथा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परन्तु भाषा के चुनाव की बाध्यता नहीं होगी।

NEP 2020 में छात्रों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है, इसी के तहत शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने को प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके।

NEP 2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (जैसे लर्निंग डिसएवेलिटीज आटिस्टिक) और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।[6]

स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूलांकन सम्बन्धी सुधार के सम्बन्ध में इस नीति में निम्नवत प्रावधान किए गए हैं–

- कला, विज्ञान व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा।
- कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इन्टर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ् यक्रम रूपरेखा (National Curricular Framework for School Education – NCFSE) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया जाएगा।

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केन्द्र' (Nationl Assessment Center) की स्थापना की जाएगी।

छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित सुधार हेतु अधोलिखित प्रावधान किए गए हैं–

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन – आंकलन के आधार पर पदोन्नति ।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक – National Professional Standard for Teachers - NPST) का विकास किया जाएगा
- राष्ट्रीय अध्यायक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या' की रूपरेखा – NCFTE) का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

21वीं शताब्दी की इस पहली शिक्षानीति में स्कूली शिक्षा की चाल ढाल को बदलने का प्रयास किया गया है। बदलते भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में यह नीति तभी सफल होगी इसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होगा। 34 वर्षों पश्चात आयी इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा एक सर्वांगीण विकसित एवं क्षमतावान् नई पीढ़ी तैयार करना है। निस्संदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने पवित्र उद्देश्यों में सफल होगी।

सन्दर्भ सूची–

1. सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी, पृष्ठ 242
2. शिक्षा, शिक्षक और समाज, डॉ0 रमेश चन्द्र, पृष्ठ 103, हाइवे सिटी नवादा मथुरा, संस्करण 2021
3. www.sdgs.un.org/goals और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुस्तिका, पृष्ठ 3, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुस्तिका पृष्ठ 3–4, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
5. वही, पृष्ठ 12
6. वही, पृष्ठ 35